

MOST IMMEDIATE

**File No. J-11011/1/2009-NREGA (Part)
Government of India
Ministry of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA Division)**

Krishi Bhawan, New Delhi.

Dated: 23rd August, 2011

To,

The Manager
Government of India Press
Ring Road, Mayapuri
New Delhi- 110064

Sir,

Hindi and English version of duly vetted Notification on amendment of Rule 7 of National Employment Guarantee Fund Rules, 2006 under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 is forwarded herewith for printing.

Yours faithfully,


(D. K. Jain)

Joint Secretary to the Government of India

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

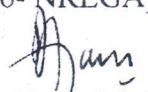
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2011

G.S.R. (E).—The following draft of certain rules to amend the National Rural Employment Guarantee Fund Rules, 2006, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 31 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, which may be received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above, will be considered by the Central Government;

The objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India, Room No. 454, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Marg, New Delhi-110001.

Draft Rules	
1.Short title and commencement —(1) These rules may be called the National Employment Guarantee Fund (Amendment) Rules, 2011.	
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.	
2. In the National Rural Employment Guarantee Fund Rules, 2006, for Rule 7, the following rule shall be substituted, namely:--	
“7. Contribution to National Fund for implementation of Schemes. —The Central Government shall contribute to the National Fund such sums of money as considered necessary for the implementation of the Schemes”.	
	[F.No. V- 28012/03/05-06- NREGA]  (D.K. Jain) Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय

तारीख : 18 अगस्त, 2011

अधिसूचना

सा.का.नि. ____ (अ).- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने और जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऐसे सभी आक्षेपों या सुझावों पर, जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, अवर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा सं० 454, कृषि भवन, डा० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) यह राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि नियम, 2006 के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“7. स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय निधि में अभिदाय - केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय निधि में धन की ऐसी राशि का अभिदाय करेगी जो स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझा जाए”।

[फा.सं.वी-28012/03/05-06-नरेगा]

डी.के.जैन

(डी.के.जैन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार